दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

बाजार समिति, करनाल और अन्य, - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता ।

1969 की सिविल रिट संख्या 1813

12 फरवरी, 1970।

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का XXIII) - धारा 12, 14 , 17 और 36 - पंजाब कृषि उपज बाजार (बाजार समितियों का चुनाव) नियम (1961) - नियम 34 - राज्य सरकार - क्या निर्धारित समय के भीतर बाजार समितियों के चुनाव आयोजित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है - ऐसे चुनाव आयोजित करने के लिए सरकार की उपेक्षा - क्या समिति के पिछले निर्वाचित सदस्यों को बाद में बने रहने का अधिकार है। तीन वर्ष और जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते - समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनके स्थान पर कोई नहीं चुना गया है - धारा 36 का सहारा लें - क्या ऐसी स्थिति में ऐसा किया जा सकता है।

पंजाब कृषि बाजार (बाजार समितियों का चुनाव) नियम, 1961 के नियम 34 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार को डिप्टी कमिश्नर को मार्केट कमेटी के चुनाव करवाने के लिए कहना है और डिप्टी कमिश्नर सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर उन्हें आयोजित करने और राज्य सरकार को उनके परिणाम की सूचना देने के लिए बाध्य है। यह इस प्रकार है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उपायुक्त को समय के भीतर चुनाव कराने के लिए कहे ताकि बाजार क्षेत्रों के लिए निर्वाचित बाजार समितियों के गठन में अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्वाचित बाजार समितियां बिना किसी विराम के अस्तित्व में बनी रहें। पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 11 में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति स्थापित करेगी और अपने मुख्यालय को निर्दिष्ट करेगी। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार बाजार समितियों की स्थापना की उपेक्षा या उपेक्षा करती है, तो अधिनियम का उद्देश्य कुंठित हो जाएगा, विशेषकर इसलिए कि बाजार समितियों को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों और शक्तियों को सौंपा गया है। (पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की बाजार समिति के सदस्यों को समय के भीतर निर्वाचित करने के लिए सरकार की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत तीन साल के लिए चुने गए बाजार समिति के पिछले सदस्यों को तीन

साल की समाप्ति के बाद और नए चुनाव होने तक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देती है। अधिनियम की धारा 17 (1) के परंतुक का एक हिस्सा काफी अस्पष्ट है, लेकिन उस हिस्से का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के तहत चुना गया बाजार समिति का प्रत्येक सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता है और इस प्रकार एक बार चुने जाने के बाद बाजार समिति के सदस्य तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक कि एक नई बाजार समिति की स्थापना नहीं हो जाती। तीन साल का। अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों पर की गई इस तरह की व्याख्या अधिनियम की धारा 14 और धारा 17 (1) और (2) में व्यक्त विधायिका के इरादे के विपरीत है।

(पैरा 3)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की अधिनियम की धारा 36 "आपातकाल" शब्द का उपयोग नहीं करती है, लेकिन कहती है, "यदि किसी भी समय राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस अधिनियम के उद्देश्यों को उसके प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है....."। इस खंड का केवल सीमांत शीर्षक ही आपातकालीन शक्तियों की बात करता है, लेकिन इस धारा में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए, राज्य सरकार को केवल यह देखना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अधिनियम के प्रयोजनों को उसके प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। यदि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर किसी को नहीं चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें अधिनियम के उद्देश्यों को उसके प्रावधानों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में धारा 36 का सहारा लिया जा सकता है।अधिनियम की धारा लागू की जा सकती है। (पैरा 5)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि 11 जून, 1969 के बोर्ड के संशोधन और अधिनियम की धारा 36 के तहत अधिसूचना जारी करने के सरकार के निर्णय को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। 1 अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रस्तावित अधिसूचना जारी न करना; और प्रतिवादी संख्या 10 को निर्देश जारी करना। 2 बाजार समिति के सचिव को दिए गए अपने मौखिक अनुदेशों को वापस लेना कि वे 19 जुलाई, 1969 से समिति के अध्यक्ष के समक्ष कागजात न रखें और सचिव को नए अनुदेश जारी करें कि वे मौजूदा निर्वाचित समिति को मान्यता दें और नए निर्वाचित सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने तक इसे सामान्य रूप से कार्य करने दें; बाजार समिति के चुनाव कराने और पूरा करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाए। करनाल में 5 सितम्बर, 1969 से पहले या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके और मौजूदा निर्वाचित समिति को तब तक कार्य करने की अनुमति देना; एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाए कि वह इस रिट याचिका का निर्णय होने तक या नव निर्वाचित समिति के कार्यभार ग्रहण करने तक मौजूदा निर्वाचित समिति के कार्यकरण में हस्तक्षेप न

**करे।कार्यालय, जो भी पहले हो।**

**याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप के साथ एन. सी. जैन, आर. एस. मित्तल और परमजीत सिंह।**

**एडवोकेट-जनरल (हरियाणा) के लिए एडवोकेट एस. सरूप, प्रतिवादी 2 के लिए एडवोकेट हरभगवान सिंह (श्रीमती आदर्श, एडवोकेट, उनके साथ)। उत्तरदाताओं के लिए।**

**निर्णय**

न्यायमूर्ति बल राज तुली - पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 12 (4) के तहत करनाल के अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय करनाल में था। इस समिति में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य शामिल थे। इसके बाद 4 अप्रैल, 1965 को बाजार समिति के चुनाव अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत आयोजित किए गए थे और याचिकाकर्ताओं 2 से 9 को निर्वाचित घोषित किया गया था। निर्वाचित सदस्यों के नाम पंजाब कृषि उपज मंडी (बाजार समितियों के चुनाव) नियम, 1961 (इसके बाद नियम कहा जाता है) के नियम 19 के उप-नियम (13) के अनुसार राजपत्रित किए गए थे। अधिनियम की धारा-12 के अनुसार, बाजार समिति के सदस्यों में से एक को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नामित किया जाना है और कृषि निरीक्षक को इस रूप में नामित किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि वास्तव में उन्होंने 5 सितंबर, 1966 को पदभार संभाला था, जिस तारीख को बाजार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी और एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया था। निर्वाचित सदस्यों ने अपने कर्तव्य में प्रवेश किया और उस तारीख को पद ग्रहण किया और यह उस तारीख से भी था कि समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया था। निर्वाचित सदस्यों में से एक, श्री किशन चंद की मृत्यु 8 जनवरी, 1967 को हो गई और उनकी मृत्यु के कारण रिक्त हुई रिक्ति में, श्री ईश्वर सिंह को अधिनियम की धारा 17 के तहत समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद बाजार समिति के लिए कोई चुनाव नहीं हुए हैं और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि वे बाजार समिति के सदस्य बने रहेंगे। जारी रखें, जबकि विपणन बोर्ड का विचार है कि बाजार समिति के निर्वाचित सदस्यों ने अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद पद धारण करना बंद कर दिया है, और इसलिए, वे बाजार समिति के सदस्यों के रूप में बने रहने के हकदार नहीं हैं। यह इन दलीलों की शुद्धता है जिसके लिए निर्णय की आवश्यकता है।

(2) अधिनियम की संबंधित धाराएं धारा 12, 14 और 17 हैं
जो निम्नानुसार पढ़ा गया है: –

> "12. (1). एक बाजार समिति नौ या सोलह सदस्यों से मिलकर बनेगी, जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्धारित करे, जिनमें से एक को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किया जा सकता है:
>
> परन्तु जहां किसी अधिसूचित बाजार क्षेत्र में एक सहकारी समिति अस्तित्व में है, समिति में दस या सत्रह सदस्य होंगे, जैसा भी मामला हो।

2. शेष सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित रीति से किया जाएगा जैसा कि इसके अंतर्गत उपबंधित किया गया है, अर्थात्-

(अ) यदि समिति में नौ सदस्य होने हैं, तो निर्वाचित किए जाएंगे-

(१) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों से पांच सदस्य, अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों द्वारा;

(२) संबंधित अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों द्वारा; और

(३) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से एक सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा;

(आ) यदि समिति दस सदस्यों से मिलकर बनती है, तो ऐसी समितियों द्वारा सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य चुना जाएगा;

(इ) यदि समिति में सोलह सदस्य होने हैं, तो निर्वाचित किए जाएंगे-

(१) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों द्वारा अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों से नौ सदस्य;

(२) संबंधित अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए धारा आईडी के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से चार सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा; और

(३) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा;

(ई) यदि समिति सत्रह सदस्यों से मिलकर बनती है, तो खंड (ग) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त निर्वाचित किया जाएगा,

ऐसी समितियों द्वारा सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य:

c/

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत चुने गए उत्पादक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अधिसूचित बाजार क्षेत्र के निवासी हैं:

'1

परन्तु जहां खंड (क) के उपखंड (iii) या खंड (ग) के उपखंड (iii) के मामले में, धारा 13 के अधीन कोई लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति नहीं है या ऐसे व्यक्तियों की संख्या चार से कम है, ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या धारा 10 और धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से चुनी जाएगी।

3. उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन इस निमित्त विहित अवधि के भीतर किया जाएगा और राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा जो दो महीने से कम नहीं होगी और उसके बाद राज्य सरकार ऐसे निर्वाचन को राजपत्र में अधिसूचित करेगी:

परन्तु यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर निर्वाचन नहीं कराया जाता है और राज्य सरकार को सूचित नहीं किया जाता है या अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को निर्वाचित और सूचित नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर समिति में अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार की गई नियुक्ति को अधिसूचित कर सकती है।

4. पूर्वगामी उपधाराओं और धारा 16 में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां पहली बार एक समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और धारा 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे सदस्य निर्धारित तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

5. समिति द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि समिति में कोई रिक्ति है या समिति के गठन में कोई दोष है।

6. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, धारा 3 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट अयोग्यताएं भी समिति का सदस्य बनने के प्रयोजनों के लिए लागू होंगी।

14. धारा 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन गठित समिति के अलावा किसी समिति का प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

17. (1) जब भी किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करना बंद कर देता है या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या धारा 15 के उपबंधों के अनुसार स्थानांतरण या हटाने के माध्यम से कोई रिक्ति होती है या अन्यथा होता है, तो राज्य सरकार धारा 12 के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सदस्य की पदावधि उसी तारीख को समाप्त हो जाएगी जिस दिन खाली करने वाले सदस्य की पदावधि समाप्त हो गई होती यदि रिक्त करने वाले सदस्य ने धारा 14 के अधीन अनुमत पूर्ण अवधि के लिए पद धारण किया होता, जब तक कि ऊपर उल्लिखित सदस्य के उत्तराधिकारी के स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति में विलम्ब न हो, जिस स्थिति में वह उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस तारीख को उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार।

2. यदि राज्य सरकार किसी मौजूदा समिति के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 करने का निर्णय लेती है, तो अतिरिक्त रिक्तियों को उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा और नियुक्त किए गए अतिरिक्त सदस्यों की पदावधि समिति के मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल का असमाप्त हिस्सा होगा।

3. राज्य सरकार ने बाजार समितियों के चुनाव कराने के प्रयोजनार्थ नियम बनाए हैं। नियम 3 में निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और प्रकाशित करने का प्रावधान है और नियम 5 से 19 में निर्वाचन कार्यक्रम और चुनाव कराने का प्रावधान है।

नियम 34 में प्रावधान है :-

"धारा 12 की उप-धारा (2) में संदर्भित सदस्यों का चुनाव उपायुक्त द्वारा उस तारीख के तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और सूचित किया जाएगा जिस तारीख को सरकार द्वारा उपायुक्त को निर्देश जारी किया गया है।

इस प्रकार इस नियम से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को बाजार समितियों के चुनाव कराने के लिए उपायुक्त को बुलाना है, और उपायुक्त उन्हें आयोजित करने और सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने की तारीख के तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को उनके परिणाम सूचित करने के लिए बाध्य है। यह इस प्रकार है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उपायुक्त को समय के भीतर चुनाव कराने के लिए कहे ताकि बाजार क्षेत्रों के लिए निर्वाचित बाजार समितियों के गठन में अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्वाचित बाजार समितियां बिना किसी विराम के अस्तित्व में बनी रहें। अधिनियम की धारा 11 में यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा (प्रत्येक अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति की स्थापना करेगी और अपना मुख्यालय निर्दिष्ट करेगी)। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार बाजार समितियों की स्थापना की उपेक्षा या उपेक्षा करती है, तो अधिनियम का उद्देश्य कुंठित हो जाएगा, विशेषकर इसलिए कि बाजार समितियों को विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों और शक्तियों को सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 36 का सहारा बहुत दुर्लभ और आकस्मिक मामलों में लिया जाना चाहिए और इसलिए नहीं कि सरकार अधिनियम के तहत अपने सांविधिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही है, बल्कि बाजार समिति के सदस्यों को समय के भीतर निर्वाचित करने के लिए सरकार की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा नहीं होती है,  मेरी राय में, अधिनियम की धारा 14 के तहत तीन साल के लिए चुने गए बाजार समिति के पिछले सदस्यों को तीन साल की समाप्ति के बाद और नए चुनाव होने तक पद पर बने रहने का अधिकार दें, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से आग्रह किया गया है। धारा 14 में विशेष रूप से प्रावधान है कि धारा 12 के तहत चुनी गई समिति का प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। एक निर्वाचित सदस्य की नियुक्ति की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन उसके चुनाव को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। हालांकि, यह धारा धारा 17 के प्रावधानों के अधीन है, जो रिक्तियों को भरने से संबंधित है। धारा 17 राज्य सरकार को धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, किसी ऐसे सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार देती है जो अधिसूचित बाजार क्षेत्र में मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, या स्थायी रूप से निवास करना बंद कर देता है या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण या हटाने के माध्यम से कोई रिक्ति होती है।  या अन्यथा, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि खाली करने वाला सदस्य समिति का सदस्य बना रहेगा, जिसका अर्थ है कि रिक्ति को धारण करने के लिए नियुक्त सदस्य का कार्यालय का कार्यकाल तीन वर्ष की मूल अवधि से अधिक नहीं होगा, जिसके लिए खाली करने वाला सदस्य रहा था।

निर्वाचित। तथापि, इस धारा के परंतुक का एक भाग है। अधिनियम की धारा 17(1) जो बिल्कुल अस्पष्ट है और परंतुक के उस भाग में लिखा है-



> "जब तक ऊपर उल्लिखित सदस्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक नए सदस्य को नियुक्त करने में देरी नहीं होती है, तब तक यह उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस दिन राज्य सरकार द्वारा उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

परंतुक के इस भाग के अधीन नियुक्त सदस्य का कार्यकाल तब तक होगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता। तथापि, यह समझ में नहीं आता है कि समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर ऐसे सदस्य बाजार समिति का गठन कैसे जारी रखेंगे। तथापि, परंतुक का यह भाग मुझे यह कहने के लिए राजी नहीं करता है कि अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अधीन निर्वाचित बाजार समिति का प्रत्येक सदस्य तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता और इस प्रकार एक बार निर्वाचित होने पर बाजार समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के बावजूद नई बाजार समिति की स्थापना होने तक पद धारण करते रहेंगे। अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों पर की गई इस तरह की व्याख्या अधिनियम की धारा 14 और धारा 17 (1) और (2) में व्यक्त विधायिका के इरादे के विपरीत है। यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां तीन साल के लिए चुनी गई पिछली बाजार समिति को सफल बनाने के लिए समय पर बाजार समिति के चुनाव आयोजित करना संभव नहीं है। पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 13(2) में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और सदस्यों की सेवानिवृत्ति के लिए बारी-बारी से प्रावधान करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है: लेकिन तीन साल से अधिक नहीं होगा। लेकिन, अगली उपधारा में प्रावधान है: -

> "उप-धारा (2) या उसके तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक निवर्तमान सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख तक पद पर बना रहेगा, जिस पर उसके उत्तराधिकारी को निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता होती है।

यदि विधायिका का इरादा था कि बाजार समिति के सदस्य तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित या नियुक्त नहीं हो जाते, तो उसने इसमें निहित प्रावधान की तरह एक प्रावधान किया होगा।

पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 13 (3)। पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों के उपनियमों में, यह प्रावधान मौजूद था कि समिति का प्रत्येक निदेशक / सदस्य तीन साल तक पद धारण करेगा, लेकिन 1968 में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा यह पाया गया कि समितियों के कई निदेशक / सदस्य नए चुनाव कराए बिना तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी पद पर बने हुए थे। इसके बाद उन्होंने सहकारी समितियों को एक परिपत्र पत्र जारी किया जिसमें उनके ध्यान में लाया गया कि उप-कानून के प्रावधानों के अनुसार समितियों के निदेशक/सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पंजाब सरकार ने "पंजाब सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश (1968 का 2)" नामक एक अध्यादेश भी जारी किया, जिसके तहत पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 26 में उप-धारा (3) के बाद उप-धारा (3-ए) को शामिल किया गया, जो निम्नानुसार है: –

> "यदि किसी कारण से सहकारी समिति की समिति के सदस्यों की संख्या समिति की बैठक के लिए सोसायटी के उप-नियमों में निर्धारित कोरम से कम हो जाती है, तो उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, रजिस्ट्रार समिति के सदस्यों की ऐसी संख्या को नामित कर सकता है जो रिक्तियों की कुल संख्या से अधिक न हो, जैसा कि वह उचित समझे। इस प्रकार नामित सदस्य तब पद धारण नहीं करेगा जब रिक्ति जिसके विरुद्ध उसे नामित किया गया है, चुनाव से भर जाती है या उसके नामांकन की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है, जो भी घटना पहले होती है।

नई उप-धारा (3-ए) की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय में एक रिट याचिका चौधरी बिशन दास और अन्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य[1] के माध्यम से चुनौती दी गई थी जो मेरे मुख्य न्यायाधीश और मेरे समक्ष सुनवाई के लिए आए थे और उसमें यह कहा गया था कि उप-धारा (3-ए) द्वारा किया गया प्रावधान कानून का एक वैध टुकड़ा था क्योंकि सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों के सदस्यों का उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद पद पर बने रहना अवैध था।

4. मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, ए . *अनंत लक्ष्मी अम्मल और एक अन्य इंडिया ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड और एक अन्य*[2] , के तहत पंजीकृत कंपनियों के संबंध में

**(एक)** आई.एल.आर. (1969) 2 Pb. &. hr. 413.
**(दो)** ए.आई.आर., 1953 एस.सी. 467.

[1] ***आई.एल.आर. (1969) 2 Pb. & hr. 413.***

[2] ए.आई.आर. 1953 एस.सी.467

भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार, जो निदेशक पिछले अवसर पर आयोजित वार्षिक बैठक में सेवानिवृत्त होने वाले थे, उन्हें उस अंतिम तिथि को अपना कार्यालय खाली करना चाहिए जिस पर वार्षिक बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी और परिणामस्वरूप वे ऐसी अंतिम तिथि के बाद निदेशक नहीं रहे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि अगली वार्षिक बैठक समय के भीतर आयोजित की गई थी या नहीं। कंपनियों से संबंधित मामला कृष्णप्रसाद *जिवालादत्त पिलानी बनाम बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष निर्णय के लिए आया* था। *कोलाबा लैंड एंड मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य*[3], और विद्वान न्यायाधीशों ने कहा: –

> "एक व्यक्ति जो एक निर्धारित समय की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति तक निदेशक नहीं रहना चाहता है, वह बच निकलने का दावा नहीं कर सकता है - ऐसी सेवानिवृत्ति केवल इसलिए कि उस समय के भीतर कानून द्वारा आवश्यक वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई गई थी। धारा 256 में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने अपना कार्यालय खाली कर दिया है: यह केवल उन निदेशकों पर लागू होता है जिन्होंने पहले से ही अपना कार्यालय खाली नहीं किया था या कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन से निदेशक नहीं थे। इसका उस अभिव्यक्ति के उचित अर्थ ोंं में निदेशक के कार्यालय के कार्यकाल से कोई लेना-देना नहीं है। धारा 256 का सीमांत नोट, जिसे हम इस खंड की प्रवृत्ति को देखने के उद्देश्य से देख सकते हैं, बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों और रिक्तियों को भरने की बात करता है। इसमें निदेशक के पद के कार्यकाल के संबंध में कोई ठोस नियम निर्धारित नहीं किया गया है। यह एकमात्र खंड नहीं है जिस पर विचार किया जाना है। हमें न केवल उस खंड से बल्कि धारा 166, 255 और 256 की भाषा से एक निर्वाचित निदेशक के पद के कार्यकाल का पता लगाना होगा।
>
> निर्वाचित निदेशक के कार्यालय के कार्यकाल के संदर्भ में, आम बैठक, जिस पर एक निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होगा, 'पद से सेवानिवृत्त होगा', हमारे निर्णय में, धारा 166 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई एक सामान्य बैठक समझी जानी चाहिए। यह देखना अत्यंत कठिन है कि वार्षिक आम बैठक न बुलाकर और धारा 256 की भाषा के तहत आश्रय लेकर पद के उस कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, किसी निर्वाचित व्यक्ति के कार्यकाल से संबंधित कोई ठोस प्रावधान निर्धारित नहीं करता है।

**(तीन)** ए.आई.आर. 1960 बोम। 312.

[3] **ए.आई.आर.** 1960 **बोम।** 312

निर्देशक। प्रतिवादी 9 और 10 के विद्वान वकील श्री भाभा ने कहा, 'हमारी राय में, यह सही है कि जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है। वैधानिक समय के भीतर आवश्यक वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने अपना कार्यालय खाली नहीं किया है क्योंकि वास्तव में वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई गई है। हमें जिन खंडों का संदर्भ पहले ही दे चुके हैं, उनका अर्थ और प्रभाव क्या है, इस पर विचार करना होगा और उन खंडों को पढ़ने के बाद, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होती है कि एक निदेशक अंतिम दिन अपना कार्यालय खाली कर देता है, जिस दिन धारा 166 के अनुसार वार्षिक बैठक बुलाई जा सकती थी।

मैं अभी-अभी संदर्भित मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं और उसी तर्क के आधार पर मैं मानता हूं कि भले ही सरकार समय पर बाजार समिति के लिए चुनाव कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहती है, पूर्व में निर्वाचित सदस्य जो नियुक्ति की तारीख से केवल तीन वर्ष के लिए पद धारण कर रहे हैं, उस अवधि की समाप्ति के बाद पद पर बने रहने का दावा इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि उनके उत्तराधिकारी के लिए कोई सदस्य नहीं चुना गया है। इस आधार पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया है कि सरकार केवल आपातकाल के मामले में अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों का सहारा ले सकती है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आपातकाल तब उत्पन्न हुआ है जब समय के भीतर चुनाव न कराने में सरकार के लापरवाह आचरण से स्थिति पैदा हुई है। विद्वान वकील "आपातकाल" शब्द के अर्थ को संदर्भित करता है जैसा कि *जनरल धर्मसभा के विदेशी मिशन के बोर्ड में* दिया गया है। *जेड ए सैमुअल*[4], सुप्रीम कोर्ट के अपने लॉर्डशिप द्वारा। उनके लॉर्डशिप के अनुसार, 'आपातकाल' शब्द का अर्थ आमतौर पर एक अप्रत्याशित घटना या परिस्थितियों का सेट होता है जो तत्काल कार्रवाई, या अचानक आवश्यकता की मांग करता है। यह "आपातकाल" शब्द का एकमात्र अर्थ नहीं है। धारा 36 "आपातकाल" शब्द का उपयोग नहीं करती है, लेकिन कहती है, "यदि किसी भी समय राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस अधिनियम के उद्देश्यों को उसके प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है,....."। इस खंड का केवल सीमांत शीर्षक ही आपातकालीन शक्तियों की बात करता है, लेकिन इस धारा में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए,राज्य सरकार को यह देखना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अधिनियम के प्रयोजनों को उसके प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। यदि निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर किसी को नहीं चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें अधिनियम के उद्देश्यों को उसके प्रावधानों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में बाजार समितियों के कामकाज को जारी रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा किए जाने से भी किसी भी तरह से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार और उसके अधिकारियों की ओर से कर्तव्य की इस तरह की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह अधिनियम

[4] 1967 के सीए नंबर 1316 पर 7 अगस्त, 1969 को फैसला लिया गया

के उद्देश्यों को कुंठित करता है, लेकिन यह उस सदस्य को, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अपने उत्तराधिकारियों के चुने जाने तक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं देता है।
6. इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे 20 जुलाई, 1969 को उनकी कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी बाजार समिति के सदस्यों के रूप में पद पर बने हुए हैं, इस तथ्य के कारण कि राज्य सरकार ने बाजार समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का विकल्प नहीं चुना है। खेद है कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अपने ज्ञापन में यह उल्लेख किया है। नहीं। 11 जून, 1969 को हरियाणा के कृषि विभाग के उप सचिव को लिखे पत्र 15243 में केवल यह बताया गया था कि मार्केट कमेटी करनाल के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष पूरे होने पर 20 जुलाई, 1969 को समाप्त हो जाएगा और 21 जुलाई से उस मार्केट कमेटी के लिए प्रशासक नियुक्त करना आवश्यक होगा। 1969. यह भी सुझाव दिया जाना चाहिए था कि उक्त बाजार समिति के नए चुनाव कराने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए। नतीजा यह है कि आज तक कोई नया चुनाव नहीं हुआ है। इस प्रकार यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें *राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 12 के अनुसार बाजार समिति का गठन करने के लिए चुनाव कराने के अपने सांविधिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए* एक परमादेश जारी किया जाना चाहिए।

7. तदनुसार, मैं इस रिट याचिका को केवल इस सीमा तक स्वीकार करता हूं कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों और इस विषय पर संगत नियमों के अनुसार चार महीने की अवधि के भीतर बाजार समिति, करनाल के नए चुनाव कराने का निदेश दिया जाए। अन्य सभी मामलों में, रिट याचिका खारिज की जाती है। चूंकि मामला कठिनाई से मुक्त नहीं था, इसलिए मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।